RNI No.: UPHIN/25/A1698

NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 109
दि. 19.08.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई।

राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सप्ताह अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में अपना आकलन साझा किया।

राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कूटनीति और संवाद के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित किया। उन्होंने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच पीएम मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सात केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ के असर का आकलन करेंगे. हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सभी सामान पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाया है.

भारतीय निर्यात पर लगेगा झटका

इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने 27 अगस्त से इस टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत तक करने की योजना भी बनाई है. माना जा रहा है कि इस फैसले से भारतीय निर्यात को तगड़ा झटका लगेगा. खासतौर पर गहने, कपड़े और जूतों जैसे सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. अनुमान है कि करीब 40 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात इस कदम से प्रभावित होगा.

क्यों अहम ये बैठक?

यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव से जूझ सकता है. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह घटनाक्रम खासा अहम माना जा रहा है. बैठक की टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं.

अमेरिका का काट खोज रहा है भारत

साथ ही, विदेश मंत्री एस. जयशंकर कुछ दिनों में रूस की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं. ऐसे में भारत एक ओर जहां अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव से निपटने की रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग और मास्को के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है.

एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देता है तो भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा. कुल मिलाकर, पीएम मोदी की यह हाई-लेवल मीटिंग भारत की आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने में बेहद अहम मानी जा रही है.

मोबाइल कॉल जितनी सस्ती हो जाएगी रसोई गैस, घर-घर पहुंचाया जाएगा : सीएम योगी

गोरखपुर (जीएनएस)। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक इस क्षेत्र में हम छह हजार मेगावाट तक पहुंचे हैं। रिन्यूवल एनर्जी के लिए किसी न किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है। यूपी में प्रचुर जल संसाधन होने के चलते इसके विकास की व्यापक संभावना है। अभी यह ऊर्जा कुछ महंगी है लेकिन आने वाले समय में यह मोबाइल फोन कॉल जितनी सस्ती हो जाएगी।

सीएम योगी रविवार को दोपहर बाद खजनी रोड पर खानीपुर गांव में टोरेंट कंपनी की तरफ से बनाए गए प्रदेश के पहले और देश के दूसरे हाइड्रोजन पॉवर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

अब तक इस क्षेत्र में हम छह हजार मेगावाट तक पहुंचे हैं। रिन्यूवल एनर्जी के लिए किसी न किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन प्लांट इस कमी को दूर करेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और बीमारियों से बचाव में ग्रीन एनर्जी की बड़ी भूमिका होने जा रही है।

इसमें यह प्लांट बड़ी भूमिका निभाएगा। टोरेंट ग्रुप के इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी-पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी। इसके बाद इसे घर-घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जाएगा।

'चुनाव आयोग का सबसे बड़ा दुश्मन खुद आयोग का मुखिया', इण्डिया ब्लाक ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

(जीएनएस)।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इण्डिया ब्लॉक ने मोर्चा खोल दिया है। वोट चोरी और बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सोमवार, 18 अगस्त को दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और वामदलों के नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग पर "पक्षपात और लापरवाही" के आरोप लगाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डीएमके के तिरुचि शिवा और वाम दलों के सांसदों ने एक स्वर में कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है।

विपक्ष का दावा है कि आयोग ने विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां अपनाई हैं।सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया, "लगता है कि सीईसी ने विपक्षी दलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। चुनाव आयोग अब सरकार की बी-टीम बन चुका है।"

इससे पहले 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष गलत सूचना और झूठ फैला रहा है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "जब राजनीति मतदाताओं को निशाना बनाकर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर की जा रही है, तो आज आयोग साफ कर देना चाहता है कि वह निडर होकर हर वर्ग और हर धर्म के मतदाताओं के साथ खड़ा है।"

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने पीएम से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा:

"थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लंबी जनसेवा और अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें जो उन्होंने हमेशा दिखाया है।"

आजाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनावो पर की विचार गोष्ठी

(जीएनएस)।

सीतापुर ' आजाद समाज पार्टी ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। संदना स्थित आंबेडकर पार्क में जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी के नेतृत्व में यह बैठक हुई। कार्यक्रम की शुरूआत बाबा साहब अंबेडकर और संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। साथ ही तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने कहा कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी जिले की सभी जिला पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। विशिष्ट अतिथि अनीस गाजी ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को चंद्रशेखर का साथ देना होगा। प्रदेश सचिव इमरान खान ने कार्यकताओं से पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। पार्टी के विधिक सलाहकार एडवोकेट अरुण कुमार राज ने बहुजन समाज को शिक्षित और संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बजाय मदिरालय खोले जा रहे हैं, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है। जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने बताया कि पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा।

कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर, प्रदेश सचिव इमरान खान भइयू, प्रदेश को कमेटी सदस्य अनीश गाजी, वरिष्ठ नेता अल्ताफ हुसैन,जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी,विधिक सलाहकार अरुण कुमार राज,विधानसभा प्रभारी श्याम लाल भारती ,जिला प्रभारी अंबुज राज, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ बिंग दिलीप जाटव, विधानसभा प्रभारी रविंद्र चौधरी, अंकित चौधरी, लाखन जाटव,अवधेश मौर्या, अनूप नास्तिक, सुमन गौतम समेत विभिन्न पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया है, जिसमें चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है।

उद्यम सखी पोर्टल यानी महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत विभिन्न वित्तीय योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और सहायक संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, विकसित करने और आगे बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।

यह एमएसएमई मंत्रालय की वित्तीय योजनाओं जैसे पीएमईजीपी; सीजीटीएमएसई; मुद्रा; ट्रेड्स आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

डीआरआई ने भोपाल में अवैध दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कारखाने का भंडाफोड़ किया; 92 करोड़ रुपये कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त; सात गिरफ्तार

(जीएनएस)।

एक महत्त्वपूर्ण खुफिया सूचना के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने भोपाल में एक गुप्त मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कारखाने का, एक सुनियोजित और समन्वित ऑपरेशन, जिसका कोड नाम "ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक" था, सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई का सहयोग किया।

डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे और इस गिरोह के सात प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया।

16.08.2025 को, ग्राम-जगदीशपुर (इस्लामनगर), हुजूर-तहसील, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित अवैध निर्माण इकाई की तलाशी में 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन (तरल रूप में) बरामद और जब्त किया गया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत ₹92 करोड़ आंकी गई। इसके अतिरिक्त, 541.53 किलोग्राम कच्चा माल, जिसमें मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमेथिलमाइन (एमएमए), हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल), और 2-ब्रोमो शामिल हैं, के साथ-साथ प्रसंस्करण उपकरणों का एक पूरा सेट भी जब्त किया गया।

एकांत परिसर में जानबूझकर चारों ओर से ढके हुए कारखाने पर डीआरआई अधिकारियों ने चतुराई से छापा मारा। मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट समेत दो लोग को अवैध उत्पादन प्रक्रिया में लिप्त पाया गया।

तत्परतापूर्वक की गई कार्रवाई में, ड्रग कार्टेल के एक प्रमुख शख्स को बस्ती, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया, जिसे भिवंडी (मुंबई) से भोपाल तक कच्चे माल की आपूर्ति की देख-रेख का काम सौंपा गया था। अवैध रूप से रसायन/ कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले दो आपूर्तिकताओं को भी मुंबई में गिरफ्तार किया गया, साथ ही मुंबई से भोपाल तक रसायनों/ कच्चे माल के परिवहन के लिए जिम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया गया।

शुरूआती जांच से यह भी पता चला है कि सूरत और मुंबई से हवाला के जरिए भोपाल में पैसा भेजा जा रहा था। पैसे के लेन-देन के लिए जिम्मेदार कार्टेल के एक करीबी सहयोगी को भी सूरत में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार किए गए सभी सात लोगों ने भारत में मेफेड्रोन नेटवर्क के एक विदेशी संचालक और सरगना के निर्देश पर मेफेड्रोन के गुप्त निर्माण में अपनी-अपनी भूमिका को स्वीकार किया।

मेफेड्रोन, एक मनोविकार नाशक पदार्थ है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। यह समाज के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि इसमें मनो-सक्रिय गुण होते हैं और माना जाता है कि यह कोकीन और एम्फैटेमिन के सेवन जैसा असर पैदा करता है।

यह पिछले एक साल में डीआरआई की ओर से बर्बाद की गई छठा गुप्त मेफेड्रोन कारखाना है। डीआरआई मादक दवाओं का निर्माण करने वाली अवैध फैक्ट्रियों को ध्वस्त करने और उनके मास्टरमाइंडों तथा इसमें शामिल अंतरराष्ट्रीय गिरोहों की तलाश में लगातार सक्रिय है।

बिहार : कांग्रेस ने 55-60 सीटों पर ठोका दावा

(जीएनएस)।

सोमवार, 18 अगस्त को दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और वामदलों के नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग पर "पक्षपात और लापरवाही" के आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डीएमके के तिरुचि शिवा और वाम दलों के सांसदों ने एक स्वर में कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है। विपक्ष का दावा है कि आयोग ने विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां अपनाई हैं।

धराली को तबाह करने वाली जगह पहुंची एसडीआरएफ, एनआईएम की टीम, तस्वीरों ने किया चौंकाने वाले खुलासे

(जीएनएस)।

उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से पूरा गांव तबाह हो गया साथ ही कई लापता हैं। जिसके लिए सर्च अभियान जारी है। धराली की आपदा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कि आखिर जिस तरह का मंजर कैमरों में कैद हुआ और प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, उसकी वजह क्या है।

वैज्ञानिक और एजेंसियां इन के कारणों का पता लगाने में भी जुट गई हैं। जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी 13 दिन से जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ, एनआईएम की संयुक्त टीम ने उस स्पॉट के कुछ विजुअल और जानकारी इकट्ठा किए। टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल तक उच्च स्तरीय रैकी एवं भौतिक निरीक्षण किया।

एसडीआरएफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ के आदेश पर सबसे पहले 7 अगस्त 2025 को मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ के नेतृत्व में

कांस्टेबल जसवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल सोहन सिंह एवं कांस्टेबल गोपाल सिंह की टीम ने धराली गांव से पैदल मार्ग द्वारा खीर गंगा के दाहिने ओर लगभग 3450 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर ड्रोन संचालन किया। खीर गंगा की पूरी निगरानी की गई, एसडीआरएफ की ओर से जानकारी दी गई कि उस जगह पर किसी भी प्रकार की झील का निर्माण नहीं पाया गया है।

धराली क्षेत्र के ऊपर बने नालों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की

जिसके वीडियो व फोटोग्राफी तत्काल उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। इसके बाद 08 अगस्त 2025 को एएसआई पंकज घिल्लियाल, मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ, मुख्य आरक्षी प्रदीप पंवार, कांस्टेबल सोहन सिंह तथा एफएम प्रवीण चौहान द्वारा श्रीकंठ पर्वत के नीचे लगभग 3900 मीटर ऊंचाई पर पुनः रैकी की गई। टीम ने ड्रोन से खीर गंगा एवं धराली क्षेत्र के ऊपर बने नालों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की और संकलित सामग्री को वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान तथा यू-कॉस्ट के वैज्ञानिकों को भेजा है।

'विरासत और स्वदेशी वस्त्र' पर दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन

वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत

(जीएनएस)।

वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत "विरासत और स्वदेशी वस्त्र" पर दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग का यह पहला अवसर है। इस कार्यक्रम में 16 देशों के 26 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), वाराणसी द्वारा 18 से 29 अगस्त, 2025 तक किया जा रहा है।

18 अगस्त, 2025 को आयोजित उद्घाटन सत्र में विकास आयुक्त (हथकरघा) डॉ. एम. बीना मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन

करते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय वस्त्रों का अध्ययन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन है। भारत की प्रत्येक बुनाई उसकी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक बुनाई एक दास्तान सुनाती है।

उन्होंने हथकरघा में समाहित स्थायित्व के महत्व और आईआईटी दिल्ली के कार्बन क्रेडिट अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि किए जाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'मूल की ओर लौटने' की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि हथकरघा को अपनाना पीछे मुड़कर देखना नहीं, बल्कि एक हरित भविष्य की तलाश है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पाठ्यक्रम 'बनारस' और भारतीय वस्त्र परंपराओं का गहन अनुभव प्रदान करेगा।

आईटीईसी कार्यक्रम, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अग्रणी और सबसे पुराना क्षमता निर्माण मंच है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और जिसके तहत 160 से अधिक देशों के 2,00,000 से अधिक अधिकारियों को नागरिक और रक्षा क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षित किया गया है।

"विरासत/स्वदेशी वस्त्र" पर आईटीईसी दो-सप्ताह का पाठ्यक्रम विभिन्न देशों के नीति निमार्ताओं, व्यवसायियों और वस्त्र पेशेवरों के लिए भारत की समृद्ध विरासत/स्वदेशी वस्त्रों का पता लगाने और वैश्विक वस्त्र बाजार में भारतीय हथकरघा क्षेत्र की अभिन्न भूमिका को समझने के लिए तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम भारतीय हथकरघा परंपराओं, उनके महत्व, तकनीकों, संरक्षण और वैश्विक व्यापार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए हथकरघा समूहों और भारत के प्रमुख संस्थानों/केंद्रों के गहन क्षेत्रीय दौरों के अवसर प्रस्तुत करता है।

आईआईएचटी, वाराणसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और नवीनतम बदलावों के बारे में तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी।

'प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी एआई-संचालित रक्त परीक्षण उपकरण का समर्थन किया'

टीडीबी ने आईओटी-सक्षम एआई-संचालित पॉइंट-ऑफ-केयर रक्त परीक्षण उपकरण के लिए मेसर्स प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड को सहयोग दिया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने मेसर्स प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 'एआई/एमएल एल्गोरिदम द्वारा संचालित किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए आईओटी-सक्षम पॉइंट-ऑफ-केयर रक्त परीक्षण उपकरण' नामक परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईआईटी गुवाहाटी के पूर्व छात्र श्री साहिल जगनानी और श्री अंकित चौधरी द्वारा स्थापित, यह कंपनी डॉक्टरों, शोधकताओं, उद्यमियों, प्रोफेसरों और छात्रों की एक बहु-विषयक टीम से उभरी है, जो वंचित आबादी के लिए किफायती नैदानिक तकनीकें विकसित करने के लिए काम कर रही है। उनके सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास, जिसे शुरू में बीआईआरएसी का सहयोग प्राप्त था, ने मोबिलैब डिवाइस का निर्माण किया—एक पोर्टेबल, बैटरी से चलने वाला क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, आईओटी-सक्षम और एआई/एमएल एल्गोरिदम द्वारा संचालित, जो किडनी, लिवर, हृदय, विटामिन और कैंसर से संबंधित 25 से अधिक मापदंडों का परीक्षण करने में सक्षम है।

कंपनी के पास आईआईटी गुवाहाटी से हस्तांतरित "पॉइंट-ऑफ-केयर क्वांटिफिकेशन के लिए एक ट्रांसमिटेंस-आधारित प्रणाली/किट" का पेटेंट है और उसने एकीकृत मिक्सर, परख विकास, सेंट्रीफ्यूज और प्रोपराइटरी ऑप्टिकल सिस्टम से संबंधित छह से ज्यादा अतिरिक्त पेटेंट आवेदन दायर किए हैं। इस उपकरण का 10,000 मरीजों पर परीक्षण हो चुका है और हाल ही में इसे सीडीएससीओ से निर्माण लाइसेंस मिला है।

यह परियोजना वर्तमान प्रोटोटाइप (एम1) को उन्नत बनाने पर केंद्रित होगी ताकि एक साथ पाँच परीक्षण किए जा सकें, रोगियों के प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके और व्यावसायिक स्तर पर विनिर्माण स्थापित किया जा सके। इस अगली पीढ़ी के मोबिलैब में हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, ग्लूकोज और जीजीटी जैसे परीक्षण शामिल होंगे।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव, श्री राजेश कुमार पाठक ने इस अवसर पर कहाः

"ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह परियोजना न केवल सामर्थ्य और पहुंच को संबोधित करती है, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी, एआई-संचालित नैदानिक समाधान विकसित करने में देश की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।"

प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों ने आभार व्यक्त करते हुए कहाः

"प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का सहयोग प्रयोगशाला नवाचार से लेकर बड़े पैमाने पर तैनाती तक की हमारी यात्रा को गति देगा। मोबिलैब के साथ, हमारा लक्ष्य ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा की कमी को पूरा करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि देश में कहीं भी, देखभाल के बिंदु पर उन्नत निदान उपलब्ध हों।"

यह सहयोग टीडीबी की आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सस्ती चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए

उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने पूरे भारत में 6.63 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत किए

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया हैः -

कारोबार में आसानी हेतु एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण 1.7.2020 से प्रभावी।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

खुदरा और थोक व्यापारियों को 2.7.2021 से एमएसएमई के रूप में शामिल करना।

एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने हेतु 9,000 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि के साथ ऋण गारंटी योजना का पुनर्गठन किया गया।

18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना का शुभारंभ।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये डालने के लिए की गई है, जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाइयाँ बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है।

90% तक गारंटी कवरेज वाले एमएसई को विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 10 करोड़ रुपये (01.04.2025 से प्रभावी) तक की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण, क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं, से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण को सुगम बनाने के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना की गई है।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे इस योजना का दायरा बढ़ गया है।

01.07.2020 से 31.07.2025 तक अखिल भारतीय स्तर पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 6.63 करोड़ है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

इण्डिया गठबंधन की ओर से कौन होगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? उद्धव ठाकरे गुट का आया बड़ा बयान

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना कर भाजपा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को सरप्राइज कर दिया है। राधाकृष्णन को एनडी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर टिकी हुई है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना यूबीटी ने इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के भावी उम्मीदवार के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है।

बता दें देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल तक रहेगा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्ष की ओर

से अभी तो उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन ठाकरे गुट ने बयान देकर सारी तस्वीर साफ कर दी है।

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसके नाम की हो रही चर्चा?

दरअसल, इंडिया गठबंधन की ओर से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को विपक्ष के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद शिवा की उम्मीदवारी का दावा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।

उद्धव ठाकरे गुट ने बताई सच्चाई?

शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि विपक्ष के नेता जल्द ही बैठक कर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी किसी नाम पर सहमति नहीं बनी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि "अभी पता नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता इकट्ठे बैठकर चर्चा करेंगे।"

कौन हैं तिरुचि शिवा?

तिरुचि शिवा एक अनुभवी राजनेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। वह तमिलनाडु से डीएमके पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नाम इसलिए चर्चा में है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से हैं।

तिरुचि शिवा ने 1996 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे। इसके बाद, वह जनवरी 2000, जुलाई 2007, 2014 और अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए।

तिरुचि एमए (अंग्रेजी) और बीएल की शिक्षा पेरियार ईवीआर कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय और तिरुचि लॉ कॉलेज, भारतीदासन विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उनकी शिक्षा और राजनीतिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

संसदीय प्रश्नः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नए नियम

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में दूषित स्थलों की पहचान और प्रबंधन के लिए 24.07.2025 को पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। संदूषित स्थलों की पहचान, निर्धारण और उपचारण की प्रक्रिया को उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

इन नियमों के अंतर्गत, संदूषित स्थल को संदूषकों से प्रभावित क्षेत्र अथवा स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा संदूषक को संदूषित स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यदि संदूषक विस्तृत स्थल मूल्यांकन पूरा करने के बाद निर्धारित प्रारंभिक स्तरों से अधिक पाया जाता है।

स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन को स्वयं या जनता से शिकायत प्राप्त होने पर, नियमों में निर्धारित जानकारी को ध्यान में रखते हुए संदूषकों से प्रभावित क्षेत्र की पहचान करने और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपने अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध दूषित स्थलों के रूप में ऐसे सभी क्षेत्रों की सूची बनाने का आदेश दिया गया है।

संदिग्ध संदूषित स्थलों की सूची प्राप्त होने पर एसपीसीबी/पीसीसी को स्वयं अथवा किसी संदर्भ संगठन के माध्यम से सूची प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर संदिग्ध संदूषित स्थल का नमूना लेकर और विश्लेषण करके संदिग्ध संदूषित स्थल का प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है। एसपीसीबी/पीसीसी संदिग्ध संदूषित स्थल को सूचीबद्ध कर सकती है क्योंकि संदूषक का संभावित संदूषित स्थल निर्धारित जांच स्तरों से अधिक पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी/पीसीसी को स्वयं अथवा किसी संदर्भ संगठन के माध्यम से संभावित संदूषित स्थल के सूचीबद्ध होने की तारीख से तीन माह के भीतर संभावित संदूषित स्थल के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तृत नमूने और विश्लेषण द्वारा संभावित संदूषित स्थल का विस्तृत स्थल मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है।

एसपीसीबी/पीसीसी विस्तृत स्थल मूल्यांकन पूरा करने के बाद स्थल को संदूषक निर्धारित अनुक्रिया स्तरों से अधिक पाए जाने पर संदूषित स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं।

एसपीसीबी/पीसीसी को केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संदूषित स्थलों की सूची प्रकाशित करने का अधिदेश दिया गया है जिसमें ऐसे प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर प्रभावित होने की संभावना वाले हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त होने पर, एसपीसीबी / पीसीसी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दूषित स्थलों की अंतिम सूची प्रकाशित करने और आम नागरिकों की जानकारी के लिए क्षेत्र में परिचालित दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस संबंध में एक नोटिस प्रकाशित करने और इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानी का भी उल्लेख करने का आदेश दिया गया है।

जिम्मेदार व्यक्ति को एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्देश की तारीख से छह महीने के भीतर एक उपचारी योजना तैयार करने, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपचारण योजना के अनुमोदन के बाद उपचारण शुरू करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

अनाथ संदूषित स्थलों और बैंकों के अस्थायी कब्जे वाले स्थलों अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में एसपीसीबी/पीसीसी को उपचारण योजना तैयार करने और उपचारी कार्यकलापों का संचालन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस संबंध में उपचारी कार्यकलापों के लिए व्यय का वहन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित अनुपात और तरीके से किया जाना है।

संसदीय प्रश्नः तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) दिशानिर्देश

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर विकास की अनुमति देते हुए तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, इकोसिस्टम के संरक्षण और मछली पकड़ने तथा अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1991 से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना लागू कर रहा है। 1991 की अधिसूचना को वर्ष 2011 में सीआरजेड/द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना से बदल दिया गया था और बाद में वर्ष 2019 में सीआरजेड/द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना द्वारा अद्यतन किया गया था। 2019 की अधिसूचना के अंतर्गत, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीआरजेडपीएस), द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजनाओं (आईसीआरजेडपीएस) या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं (आईआईएमपीएस) को अपडेट करना होगा और उन्हें अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा, जब तक इन नई योजनाओं को अनुमोदित नहीं किया जाता है, सीआरजेड / आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधान लागू रहेंगे। अब तक, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के लिए नए सीजेडएमपी और ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के लिए आईसीआरजेडपी को मंजूरी दी गई है।

सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत सीजेडएमपी का नई सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुलग्नक- क्ष में निर्धारित दिशानिदेर्शों के अनुसार है, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच किसी भी अंतर के बिना पूरे देश में लागू हैं। तटीय जोन प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को अपडेट करने के लिए दिशा-निदेर्शों के अनुरूप अपेक्षित अध्ययन और सर्वेक्षण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मंत्रालय के प्राधिकृत संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

सीआरजेड अधिसूचनाओं, 2011 और 2019 का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने देश में उल्लंघनों से निपटने और सीआरजेड विनियमों को लागू करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

आन्ध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (एपीसीजेडएमए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उल्लंघन के कुल 53 मामलों की सूचना मिली है जिनमें से किसी में भी बार-बार अपराध करने वाले शामिल नहीं हैं। बापतला जिले सहित जिले के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैंः

जिला या ब्लॉक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी

(जीएनएस)।

भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित संकेतकों का उपयोग करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो देश की विशिष्ट प्राथमिकताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। इस संबंध में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करने के प्रयास के तहत सतत विकास लक्ष्यों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ संरेखित किया है। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कल्याण व विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है, जो सतत विकास लक्ष्यों के आदर्श वाक्य "कोई भी पीछे न छूटने पाए" के अनुरूप "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के प्रति अपनी व्यापक वचनबद्धता से प्रेरित है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, जिला और स्थानीय सरकार के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा एवं निरंतरता की प्राथमिक जिम्मेदारी रखते हैं। अपनी उपलब्धियों पर प्रभावी रूप से निगाह रखने के उद्देश्य से राज्यों को उनकी विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं, डेटा आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और संसाधन उपलब्धता के अनुसार अपने स्वयं के राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग, जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति की निगरानी हेतु जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) विकसित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। इसे मान्यता देते हुए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य निगरानी ढांचे के निर्माण, समीक्षा और परिशोधन में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रयास में वर्ष 2019 में, मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निगरानी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए और प्रसारित किए। दिशानिर्देश का बाद में मार्च 2022 में "उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी पर निगरानी ढांचे पर मार्गदर्शन" शीर्षक वाली रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अद्यतन किया गया।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

जीओआईस्टैट्स मोबाइल एप्लिकेशन की विशेषताएं और इस्तेमाल

(जीएनएस)।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों की प्रदान करने के उद्देश्य से 29 जून, 2025 को जीओआईस्टैट्स ऐप शुरू किया गया था। तदनुसार, चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े इस ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पोर्टल में वर्तमान में छह डोमेन हैं, जिनमें नौ संकेतक शामिल हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीओआईस्टैट्स ऐप के उपयोग के आंकड़े रखता है। 11 अगस्त, 2025 तक जीओआईस्टैट्स ऐप के 8040 डाउनलोड हैं। यह एप्लिकेशन डेटा पृथक्करण की सुविधाओं के माध्यम से सहायता करता है। वर्तमान में, ऐप में डेटा सीमित रूप से उपलब्ध है, क्योंकि ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी आधारित डेटा प्रदान करना है। इसके अलावा, ई-सांख्यिकी पोर्टल पर उपलब्ध पृथक डेटा तक पहुंचने के लिए ऐप पर लिंक प्रदान किए गए हैं। चयनित संकेतक का समय श्रृंखला दृश्य ऐप पर दिया गया है।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

देश में बढ़ता सड़कों का जाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर के दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये दो परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली खण्ड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-छ्छे। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण स्तर को घटाना है। इन दोनों परियोजनाओं की लागत 11000 करोड़ रुपए है जिसमें द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली खण्ड के लिए 5,360 करोड़ और अर्बन एक्सटेंशन रोड-छ्छे के लिए 5,580 करोड़ का खर्च आया है।

वैसे तो यातायात सुविधाओं के लिए राजपथ का निर्माण सभी सरकारों की प्रथमिकता रही है किन्तु आजकल के आर्थिक युग में राजपथों का महत्व काफी बढ़ गया है। जरूरतों के मुताबिक राजमार्गों पर ट्रकों, बसों और कारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यदि राजमार्गों के जाल में विस्तार नहीं होगा तो भारत विश्व विकास की दौड़ से पिछड़ जाएगा।

दूरदर्शा राजनेता वही है जो कल की जरूरतों का एहसास करे। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन हो या उसके पहले के शासक। किसी भी उद्देश्य के लिए राजमार्गों की जरूरतों को महसूस करके उन्होंने सड़कें बनवाई थीं। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने भी कनेक्टिविटी के विस्तार का काम किया। पंचवर्षीय योजनाओं में बजट निर्धारण करके राजमार्गों के निर्माण हेतु न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों भी ढांचागत विकास के लिए राजमार्गों के निर्माण के लिए हमेशा ही तत्परता दिखाई है। तुलनात्मक अध्ययन से यह जरूर स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार लम्बी दूरी के राजमार्गों का जाल बिछाने में ज्यादा रुचि ले रही है क्योंकि राजमार्ग निर्माण आज व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनिवार्य जरूरत बन गया है। किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के मानदंड समय, जरूरत और राजस्व सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आजादी के तुरन्त बाद तो देश को बहुत जरूरत थी राजमार्गों की किन्तु उस वक्त देश के पास इतना धन नहीं था कि हर राज्य में लम्बी दूरी राजमार्गों का निर्माण हो सके।

दरअसल वेंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण होते हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी यानि सार्वजनिक कार्य विभाग से राज्य सरकारें सड़क निर्माण का कार्य कराती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतें गांवों में सड़क निर्माण और रखरखाव का काम करती हैं।

धनाभाव में वेंद्र सरकारें न तो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर इतना खर्च कर पाती थी और न ही राज्य सरकारें अपने संसाधनों से सड़क निर्माण कराने में बहुत ज्यादा समर्थ थीं। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वेंद्र सरकार जिन राजमार्गों को बना रहा है वह तो वेंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के अंतर्गत है ही राज्य सरकारें भी वेंद्र की ही मदद से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राज्यों में सड़कों का जाल बिछा रही हैं। यही नहीं ग्राम पंचायतों को भी वेंद्र सरकार से ही धन मिल रहा है।

बहरहाल किसी भी देश का विकास जानने के लिए वहां की सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों की गणना की जाती है। शहरों के विकास के लिए आजकल मेट्रो रेल होना आवश्यक हो गया है उसी तरह एक राज्य से दूसरे-तीसरे और चौथे के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है और इस सरकार के वेंद्रीय भूतल परिवहन विभाग ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ कई-कई राज्यों को जोड़कर सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

यह एक संयोग ही है कि सभी राज्य चाहे वे किसी भी पाटा के हों, सभी वेंद्रीय परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से खुश हैं और यथासंभव वेंद्र के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। सबसे जीवंत उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य के तमाम राजमार्ग संकरे और खतरनाक मोड़ वाले थे। वेंद्रीय भूतल परिवहन ने टनल, फ्लाई ओवर और खतरनाक मोड़ों को चौड़ा करके इतना सुगम बना दिया है कि अब राज्य की परिवहन व्यवस्था काफी सुचारू होने लगी है।

नकली खाद-बीज की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश

नकली खाद-बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएं- श्री शिवराज सिंह

एक नहीं, सैकड़ों किसान हो रहे हैं परेशान, किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझें- श्री शिवराज सिंह

नकली खाद, बीज और कीटनाशक किसानों के लिए अभिशाप है- श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रूख अपनाया है। श्री शिवराज सिंह ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वरिष्ठ अधिकारियों की इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक लेकर नकली खाद-बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की फसलें खराब होने को सभी अधिकारी अत्यंत गंभीरता से अधिकारी लें, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सकें। श्री शिवराज सिंह ने व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि नकली खाद-बीज और कीटनाशकों के कारण कोई एक नहीं, बल्कि विभिन्न जिलों में सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें आती है, किसान बोलते हैं कि खेत में दवाई डाल रहे हैं पर इसका असर नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत चिंतित हूं। इन किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि मैंने कल खुद किसान के खेत में जाकर देखा, एक दवाई किसान ने डाली, जिसके कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कल जब मैंने खेत में देखा तो

सैकड़ों किसान वहां मौजूद थे। इन सबने मुझे शिकायतें की, परेशानी बताईं। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसे घटिया या नकली दवाई और खाद-बीज बेचने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कृषि अधिकारियों से इस संबंध में अब-तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए कहा कि नकली खाद, बीज और कीटनाशक किसानों के लिए अभिशाप है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम हमारे किसानों को लूटते हुए नहीं देख सकते।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग का अमला राज्य सरकारों के साथ किसानों के खेतों में जाकर जांच करें और अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर आकस्मिक छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई करें। सैंपल लिए जाएं व फेल होने पर कार्रवाई करें। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि जो कंपनी या निमार्ता गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे तो गड़बड़ करने वाले लोगों में भय पैदा होगा और किसानों को राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर फैक्ट्रियां व दुकानें सील की जाएं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो किसानों के हित में कड़ी कार्रवाई करना हमारा धर्म है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो नहीं होने दें, यह हमारी ड्यूटी है, जिसका पालन हमें करना है। श्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में किसानों की शिकायतों को भी सुनने के साथ उनका पूरा समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि प्राप्त शिकायतों की वे स्वयं नियमित समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बात करके किसानों के मामले में पूरी संवेदना के साथ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। श्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार भी व्यापक रूप से करने के दिशा-निर्देश दिए, ताकि किसान परेशान होने से बच सकें।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी किसानों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाएं, ताकि किसान नुकसान और परेशानी से बच सकें। श्री शिवराज सिंह ने एक अन्य विषय में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सहायता का कृषि विभाग की टीमों के द्वारा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चेक किया जाना चाहिए कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र से दी जा रही सब्सिडी का लाभ किसानों को वास्तविक रूप से कितना मिल रहा है।

आईबीसी ने व्यापार सुगमता और परिसंपत्ति प्राप्ति को बढ़ावा दिया

आईबीसी के अंतर्गत 1,194 कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, इससे लेनदारों को ₹3.89 लाख करोड़ की वसूली संभव हुई

दिवालियापन ढाँचे को मजबूत करने और देरी को कम करने के लिए छह विधायी संशोधन और 100 से ज्यादा नियामक बदलाव किए गए

वित्त वर्ष 2024-25 में बैंकों की लगभग आधी वसूली आईबीसी के खाते में होगी

(जीएनएस)।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने भारत के दिवाला ढाँचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की प्रमुख उपलब्धि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनियों का समाधान करने और लेनदारों द्वारा वसूली करने की इसकी क्षमता रही है। पुनरुद्धार के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध ढाँचा प्रदान करके, आईबीसी ने लेनदारों का विश्वास मजबूत किया है और घरेलू तथा विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित किया है। आईबीसी ने भारत में व्यापार करने की सुगमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक तेज और अधिक संरचित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है। इससे परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम हो रहा है, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल रहा है, ऋण की उपलब्धता बढ़ रही है और सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बना रहा है। 31 मार्च, 2025 तक आईबीसी ढांचे के अंतर्गत कुल 1,194 कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। इन मामलों के माध्यम से लेनदारों को ₹3.89 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश के समय मूल्यांकन किए गए इन कंपनियों के परिशोधन

मूल्य के 170 प्रतिशत से अधिक और उचित मूल्य के 93 प्रतिशत से अधिक है।

आईबीसी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2025) के अनुसार सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह मार्च 2025 के अंत तक 2.3 प्रतिशत के बहु-दशकीय निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है। यह कमी एक मजबूत और अधिक स्थिर बैंकिंग प्रणाली का संकेत देती है। 2023-24 के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर आरबीआई की (26 दिसंबर 2024 को जारी) रिपोर्ट के अनुसार है कि एससीबी ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल ₹96,325 करोड़ की वसूली की। इसमें से अकेले आईबीसी चैनल ने ₹46,340 करोड़ का महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कुल वसूलियों का

48.1 प्रतिशत है। सरकार ने आईबीसी में छह विधायी संशोधन किए हैं और इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव किए हैं। ताकि दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत किया जा सके और प्रक्रियात्मक दक्षता को बढ़ाया जा सके जिससे देरी को कम किया जा सके।

आईबीसी ने कंपनियों और उनके देनदारों के बीच व्यवहारिक बदलाव लाया है। चूक करने वाली कंपनियां स्वामित्व खो सकती हैं यह विश्वसनीय खतरा पैदा करके इस संहिता ने देनदारों और लेनदारों के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया है।

दिवाला पेशेवरों (आईपी) की क्षमता निर्माण के लिए कई पहल की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने व्यावहारिक कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की। इसने प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्व बैंक, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के संस्थान (आईआईसीए) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जैसे विशेषज्ञ निकायों के साथ भी सहयोग किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया, जिससे आईपी को सर्वोत्तम प्रथाओं का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ।

यह जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और जमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज लोकसभा में दी।

₹74,052 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं की समीक्षा की गई

परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी), डीपीआईआईटी ने महाराष्ट्र में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की अध्यक्षता की

शहरी परिवहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएमजी ने एमयूटीपी चरण-IIIE और सिनारमास पश्चिम तट परियोजना की समीक्षा की

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र राज्य में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की एक उच्च-स्तरीय बैठक 14.08.2025 को आयोजित की गई।

23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कुल 28 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत ₹74,052 करोड़ से अधिक है। ये परियोजनाएँ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनमें रेलवे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समीक्षा की गई परियोजनाओं में, ₹33,690 करोड़ के निवेश वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण-IIIE पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल क्षमता को बेहतर करना, भीड़भाड़ कम करना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। इस

परियोजना में भारत की वित्तीय राजधानी में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण, सिग्नलिंग प्रणालियों का आधुनिकीकरण और नए रोलिंग स्टॉक की खरीद शामिल है।

रायगढ़ जिले में ₹10,500 करोड़ के निवेश वाली एक प्रमुख औद्योगिक पहल, सिनारमास पश्चिम तट परियोजना की भी समीक्षा की गई। सिनारमास पल्प एंड पेपर की यह परियोजना भारत की लुगदी और कागज निर्माण क्षमता को बेहतर करेगी, जरूरी रोजगार पैदा करेगी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को आकर्षित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करना है।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो ने की और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की ओर से सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डीपीआईआईटी के प्रधान आर्थिक सलाहकार ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सक्रिय रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से अपनी चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.i»»f/) की इस विशिष्ट व्यवस्था का लाभ उठाने वाले निजी सहयोगियों के महत्व पर जोर दिया।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत

विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुधार एजेंडे का विस्तार करता है

16 अधिनियमों के 288 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया

76 मामलों में पहली बार उल्लंघन करने पर सलाह या चेतावनी दी जाएगी

यह विधेयक छोटे दंडों को तर्क पर आधारित बनाता है, बार-बार अपराध करने पर दंड में बढ़ोतरी करता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक को पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किया जा चुका है। माननीय मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से विधेयक को सेलेक्ट कमिटी को भेजने का अनुरोध भी किया है। समिति के सदस्यों का चयन माननीय अध्यक्ष की ओर से किया जाएगा और समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह प्रक्रिया जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 की सफलता पर आधारित है - जो विभिन्न अधिनियमों में छोटे अपराधों को व्यवस्थित रूप से अपराधमुक्त करने वाला पहला समेकित कानून है। 11 अगस्त 2023 को अधिसूचित 2023 अधिनियम ने 19 मंत्रालयों/ विभागों की ओर से प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया।

2025 विधेयक इस सुधार एजेंडे का विस्तार करते हुए 10 मंत्रालयों/ विभागों की ओर से प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों को इसमें शामिल करता है। कुल 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है - 288 प्रावधानों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-अपराधीकरण किया जाएगा, और 67 प्रावधानों में जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 में जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 (एनडीएमसी अधिनियम) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 67 संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:

पहली बार उल्लंघनः 10 अधिनियमों के अंतर्गत 76 अपराधों के लिए सलाह या चेतावनी। गैर-अपराधीकरणः मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास की धाराओं को मौद्रिक दंड या चेतावनी से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दंडों का युक्तिकरणः दंड को आनुपात पर आधारित बनाया जाएगा, और बार-बार होने वाले अपराधों के लिए क्रमिक दंड दिया जाएगा।

न्यायनिर्णयन तंत्रः प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए दंड लगाने के लिए नामित अधिकारियों को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्यायिक बोझ कम होगा।

जुमार्ने और दंड में संशोधनः विधायी संशोधनों के बिना निवारण बनाए रखने के लिए हर तीन साल में स्वचालित रूप से 10% की बढ़ोतरी।

चाय अधिनियम, 1953, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, जैसे चार अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम, 2023 का हिस्सा थे और वर्तमान विधेयक के अंतर्गत इनका और अधिक गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के लिए पंजीकरण की सुविधा हेतु पोर्टल, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी

लगभग ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव हो गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।

यह योजना नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नव-नियोजित युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

योजना के भाग अ के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किए जाएँगे। भाग इ के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

नियोक्ता अब प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfi»»fdia.gov.in [1]ff https:// pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सभी पहली बार नौकरी करने वालों को उमंग ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक भाविना पटेल ने अमरीका के स्पोकेन में आईटीटीएफ विश्व पैरा इवेंट्स में इतिहास रचा

भाविना ने आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा एलीट स्पर्धा में स्वर्ण और आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में महिला एकल वर्ग 4-5 श्रेणी में रजत पदक जीता

दो पदकों की जीत ने भाविना को टेबल टेनिस की महिला एकल श्रेणी के व्हीलचेयर (क्लास 1 से 5) में आईटीटीएफ विश्व पैरा रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा दिया

(जीएनएस)।

अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक सुश्री भाविना पटेल ने अमरीका में वाशिंगटन के स्पोकेन में आयोजित दो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शीर्ष सम्मान हासिल करके भारत को बहुत गौरवान्वित किया है।

भाविना ने 9 से 13 अगस्त 2025 तक, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) विश्व पैरा एलीट स्पर्धा में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए महिला एकल वर्ग 4-5 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। यह जीत दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों के सामने उनके असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक खेल कौशल का परिणाम है।

भाविना ने इससे कुछ ही दिन पहले, 6 से 8 अगस्त 2025 तक स्पोकेन में ही आयोजित आईटीटीएफ

वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में के इसी वर्ग में रजत पदक जीता था, जिससे वैश्विक मंच पर उनकी निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी बढ़ गई है।

सुश्री भाविना पटेल लगातार दो बार पोडियम पर स्थान पाने के साथ ही अब पैरा टेबल टेनिस में क्लास 1 से 5 तक की महिला श्रेणियों में महिला सिंगल्स के लिए विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं - जो भारतीय खेलों में एक ऐतिहासिक क्षण है और उत्कृष्टता के संदर्भ में उनकी अथक मेहनत का प्रमाण है।

भाविना पटेल की ये उपलब्धियां व्यक्तिगत विजय से कहीं आगे हैं और वे देश भर के एथलीटों, विशेषकर पैरा-खेल क्षेत्र के एथलीटों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। वे इस विश्वास को मजबूत करती हैं कि समर्पण और दृढ़ता से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी संगठनात्मक संस्कृति के भाग के रूप में सदैव अपने कर्मचारियों को खेल और शारीरिक फिटनेस गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया व समर्थन दिया है। निगम का मानना है कि कर्मचारियों में खेल भावना को बढ़ावा देने से न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान मिलता है, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क तथा दृढ़ता जैसे मूल्यों का भी विकास होता है, जो कार्यस्थल पर प्रदर्शन को बेहतर करते हैं। पिछले कई वर्षों से, ईएसआईसी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एवंअंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और संगठन खेल उपलब्धियों के लिए संसाधनों, अवकाश तथा मान्यता के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

भाविना पटेल की ऐतिहासिक सफलता इस बात का गौरवपूर्ण उदाहरण है कि कैसे निगम का खेलों के प्रति सहयोग कर्मचारियों को अपने जुनून के साथ अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे वे विश्व मंच पर चमकने में सक्षम हो सकते हैं।

नारी शक्ति सम्मान समारोह एवं इंडियाज माई बेस्ट टैलेंट हंट शो का आयोजन हुआ संपन्न

(जीएनएस)।

विमेंस स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी वाराणसी द्वारा 151 महिलाओं को नारी शक्ति एवं काशी की शान सम्मान से सोनी जायसवाल समाज सेविका द्वारा सम्मानित किया गया।

नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि श्रीमती मीना चौबे भाजपा प्रदेश मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती नम्रता चौरसिया डायरेक्टर उपभोक्ता सहकारी संघ उत्तर प्रदेश रही साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत माई टैलेंट हंट शो का कार्यक्रम भी रहा जिसका उद्घाटन विशिष्ट अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करा कर किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डांस प्रतियोगिता फैशन डिजाइनर ड्रेस प्रतियोगिता यूनिक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता मेकअप हेयर स्टाइल प्रतियोगिता कराया गया।

कार्यक्रम के मुख्य जज डांस के कत्थक नृत्यांगना श्रीमति ममता टंडन एवं पूजा शिव शक्ति फाउंडेशन की डांस टीचर रही और फैशन फील्ड से प्रदीप सिंह इवेंट ऑर्गनाइजर डॉ आकांक्षा त्रिवेदी मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 23 और सेलिब्रिटी सिंगर नवाब वी.के सिंह रहे साथ ही कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण मैजिक शो बेस्ट मैजिशियन मनीष के मैजिक द्वारा मनोरंजन कराया गया। इंद्रेशियां फैशन डिजाइनर द्वारा पारंपरिक राजवाड़ा थीम वस्त्रों का प्रदर्शन मॉडल द्वारा करा कर काशी की कलाकारी को और इंडोवेस्टर्न ड्रेस को रैंप पर दशार्या गया। जो कार्यक्रम का मुख्य बिंदु बना रहा और काशी नगरी कला की नगरी है इनके अंदर टैलेंट की भरमार है और टैलेंट को सभी बच्चों ने अपने नृत्य कर इंडियन वेस्टर्न डांस कर अपने अपने टैलेंट और प्रतिभा के समागम को मंच पर दिखाया और कार्यक्रम में श्रीमति सोनी जायसवाल ने सभी अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और सभी विनर बच्चों को इंडिया जबेस्ट डांसर बेस्ट मेकअप बेस्ट हेयर स्टाइल बेस्ट फैशन ड्रेस डिजाइनर बेस्ट मॉडल अवॉर्ड गिफ्ट मेडल दिया साथ ही सभी प्रतिभागी बच्चों को भी सर्टिफिकेट दे कर सम्मानित करते हुए बच्चों महिलाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में सहयोगी पार्टनर संकल्प बनारस होटल सीस सेंस होटल फोटो ग्राफर इवेंट ऑर्गनाइजर आदि रहे और संस्था से कविता अनुपमा आरती राय रेखा वंदना सौरभ अग्रवाल आशुतोष विकास शाह ऋष पांडे एमी पाण्डेय मयंक श्रीवास्तव आदि का सहयोग रहा कार्यक्रम का संचालन एंकर आदित्य केशरी ने किया। इंडिया जबेस्ट डांसर 2025 का खिताब गया। प्रांजला नंदिनी ठाकर मनोज कन्नौजिया अजय पटेल मोनू सोनकर प्रियांशु इंडिया जबेस्ट फैशन डिजाइनर 2025 इंद्रेशियां फैशन अमित पांडे मयंक पांडे चंद्रकांती ऋष पांडे मोनिका शर्मा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयान त्रिवेदी इंडिया जबेस्ट मेकअप अवार्ड 2025 प्रियांशु इंडिया जबेस्ट मॉडल अवॉर्ड 2025 दीक्षा श्रीवास्तव नंदिनी ठाकर मानव कपूर इंडियाज बेस्ट फोटो ग्राफी अवॉर्ड रोशन वर्मा फिक्स फ्रेम स्टूडियो अर्पित वर्मा युवराज सिंह युवी फ्लिक्स फोटोग्राफी इंडियाज बेस्ट होटल अवॉर्ड संकल्प बनारस होटल सीस सेंस होटल इंडियाज बेस्ट मैजिशियन अवॉर्ड जादूगर मनीष नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम में नामित किए गए। सारिका दुबे समाज सेविका मीनू ग्रोवर समाज सेविका नेहा अग्रवाल समाज सेविका सत्या जायसवाल समाज सेविका रेखा जायसवाल समाज सेविका गरिमा पाण्डेय समाज सेविका खुशी वर्मा समाज सेविका रीमा जायसवाल समाज सेविका ममता जायसवाल समाज सेविका माया जायसवाल समाज सेविका अल्बिना सरदार समाज सेविका मंजू जायसवाल समाज सेविका दीपा बरनवाल मेकअप आर्टिस्ट इला पाण्डेय अभिनेत्री एवं फिल्म प्रोड्यूसर अदिती गुलाटी शिक्षा विभाग सुमन सिंह शिक्षा विभाग रूबी जायसवाल समाज सेविका सविता सिंह समाज सेविका रेनू पांडे समाज सेविका अंजू सिंह समाज सेविका अनीता सिंह समाज सेविका अर्चना सिंह समाज सेविका रीता जायसवाल समाज सेविका वंदना जायसवाल समाज सेविका अंकिता जेटली समाज सेविका ताइक्वांडो नीलू रुपानी समाज सेविका अंजू सेक्सरिया समाज सेविका अंशु चौधरी समाज सेविका श्रुति जैन समाज सेविका सौम्या अग्रवाल समाज सेविका स्वाति जायसवाल समाज सेविका सुनीता भार्गव समाज सेविका सारिका गुप्ता समाज सेविका संगीता अग्रवाल बिजनेस वूमेंस आरती पाठक समाज सेविका मीनू उपाध्याय समाज सेविका अनुपमा जायसवाल समाज सेविका मधु सिंह समाज सेविका रुचि शाह समाज सेविका वंदना रघुवंशी समाज सेविका मीना श्रीवास्तव समाज सेविका सीमा गिरी शिक्षा विभाग अनामिका विश्वकर्मा समाज सेविका रिचा सिंह समाज सेविका दीपा गुप्ता खिलाड़ी विनीता सिंह शिक्षा विभाग नीलू गुलाटी शिक्षा विभाग एकता त्रिवेदी फिटनेस ओजस्वी शर्मा एंकर नायला बशीर ब्यूटीशियन इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही.

मकनपुर शरीफ में उर्स अबुल वकार व उर्स अमीरुल औलिया 19-20 अगस्त को, तैयारी हुई तेज

कानपुर नगर- दारुन्नूर मकनपुर शरीफ में विगत वर्षों की भांति इस साल भी परम्परा के अनुसार एक विशाल रूहानी इज्तिमा आयोजित होने जा रहा है। हजरत कुत्बे आलम सैयद अबुल वकार कल्बे अली रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अमीरुल औलिया सैयद मंजर अली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 19 और 20 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा।

कुत्बे आलम और अमीरुल औलिया की रूहानी सेवाएँ हजरत सैयद अबुल वकार कल्बे अली रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के महान दाई-ए-इस्लाम और मुबलिग-ए-मदारियत थे। अल्लाह ने आपको

रूहानियत में इतना बुलंद मकाम दिया कि आप "कुत्बे आलम" के लकब से मशहूर हुए।आपके फरजंदे अरजमंद हजरत सैयद मंजर अली रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदे मोहतरम की तर्बियत से फैज हासिल कर "अमीरुल औलिया" का लकब पाया। दोनों बुजुर्गों की ज़िन्दगी बरकत और फैज का चश्मा रही और आज भी इनके मजार पर जाएरीन को रूहानी सुकून नसीब होता है।उर्स के सभी इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क के अलगझअलग इलाकों से जलीलुल-कदर उलमा और मशाइख शरीक होंगे।

इनमें शैखे तरीकत हजरत कारी सैयद महजर अली वकारी मदारी, हजरत सैयद अजहर अली वकारी मदारी, हजरत सैयद आले गौस समदानी मियाँ किछौछा शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ़्ती फैज हसन सफवी सफीपुर शरीफ, हजरत मुफ़्ती मोहम्मद आसिफ मुजद्ददी कन्नौज,अल्लामा असलम मीनाई कलकत्ता , मुफ्ती शफीकुल कादरी मुम्बई,मुफ्ती काशिफ सईद बहेड़ी और दूसरे नामवर उलमा शामिल हैं।यह जानकारी सैयद शाजिर अली जाफरी ने देते हुए बताया है उर्स की तकरीबात में आम व खास की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। नात, ज़िक्र व अजकार और दुआई इज्तिमात से यह आयोजन एक रूहानी माहौल में ढल जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक, जाएरीन के लिए रहाइश, खाना और सहूलियतों का भी खास बंदोबस्त किया गया है।इस मौके पर हजरत अल्लामा मुफ़्ती मोहम्मद आरिफ मंजरी अल-अजहरी साहब की दो नई किताबों का आगाज किया जाएगा। इंतजामिया ने तमाम मुहिब्बाने औलिया से अपील की है कि वे बड़ी तादाद में शिरकत कर के इस रूहानी इज्तिमा को कामयाब बनाएँ और औलिया-ए-किराम के फैज व बरकत से अपने दिलों को रोशन करें।

नगर में आज मिठाइयों के व्यपारियो में रही हलचल

(जीएनएस)।

स्योहारा में उस समय अफरातफरी मच गई जब फूड अधिकारी ने रमाकांत मिष्ठान भंडार मील के सामने की दुकान से मिठाई के सम्पल लिए। इस खबर को सुनकर कुछ मिठाई वाले दुकान बंदकर भाग गए। मिली जानकारी के अनुसार आर के सिंह अधिकारी ने बताया कुछ शिकायत कर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल

पर डाली शिकायत। जिस कारण हमने लिए है नगर के कुछ दुकानों से मिठाई के सम्पल। वही अधिकारी ने सम्पल को होटल पर बैठकर लगाई सील।बिजनोर से आये अधिकारी ने कहा मिलावट पाई गई तो सख्त की जाएगी कार्यवाही।

गांव बक्शीवाला मे गैस सिलेंडर लीक होने से लगी भयंकर आग।

(जीएनएस)।

बिजनोर क्षेत्र कोतवाली इकबाल के घर मे खाना बनाते समय लगी भयंकर आग। आग लगने से घर मे मची अफरा तफरी मोहल्ले वासी मौके पर पहुंचे। आग लगने से हुआ 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान। इस हादसे मे नही हुई किसी भी तरह की जनहानि। सूचना मिलने पर फायर बिर्गेड की टीम भी मौके पर पहुंची।बिजनौर कोतवाली शहर के मोहल्ला बक्शीवाला का पूरा मामला

बताया गया है।

भारतीय किसान संगठन ने केम्प लगाकर बढ़ाया अपना कुनबा

(जीएनएस)।

हापुड़ शाहनवाज चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष उ० प्र० भारतीय किसान संगठन के कैम्प कार्यालय पर आगमन हुआ किसान नेता बड़े भाई राजेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन ओर लोकेश नागर जिलाध्यक्ष गाजियाबाद मोके पर मौजूद रहे इमरान चौधरी प्रदेश महासिचव उ० प्र० व ओर ताज मौहम्मद मुरादपुर वालो की भारतीय किसान संगठन मे घर वापसी की

संस्कार कराटे क्लासेज साकेत नगर में ब्लैक बेल्ट टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई।

(जीएनएस)।

9 एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स द्वारा दिनांक 18 अगस्त को संस्कार कराटे क्लासेज साकेत नगर में ब्लैक बेल्ट टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 09 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन 1 बच्चे ने ब्लैक बेल्ट सेकण्ड डेन और 1 बच्चे ने ब्लैक बेल्ट 3१थर्ड डेन की परीक्षा उतीर्ण की है।

ब्लैकबेल्ट थर्ड डेन ज्योति सोनकर

ब्लैकबेल्ट सेकण्ड डेन गौरांग पॉल

ब्लैकबेल्ट फर्स्ट डैन डॉ प्रखर जायसवाल

ऋचा सिंह अनुश्री त्रिपाठी आराध्या ठाकुर तेजश्वी मौर्या

सत्यम ठाकुर अर्श मिश्रा चारवी अग्रवाल, सहान जागृति यादव सेंसेई राजकुमार सेंसेई हर्ष और 9 एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक रेन्शी अमित कुमार उपाध्याय ने यह परीक्षा ली इस परीक्षा में काटा कुमिते किहान लिखित परीक्षा आदि के सत्र हुए।

गाजियाबाद के कस्बा फरीदनगर मे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति तिरंगा यात्रा निकाली गई

(जीएनएस)।

गाजियाबाद के थाना भोजपुर के कस्बा फरीदनगर मे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति द्वारा आज भव्य "तिरंगा यात्रा" का आयोजन युवा जिला अध्यक्ष रोहित तोमर और कुलदीप शर्मा अध्यक्ष मेरठ मंडल युवा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर देशप्रेम का अद्भुत प्रदर्शन किया। यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनमानस में देशभक्ति की भावना का संचार करना था।यात्रा की शुरूआत महमदपुर गेट से लेकर कस्बा फरीदनगर मेंन मार्केट और बस स्टैंड से होते हुए ग्राम भोजपुर थाने के पास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति पर पुष्प माला अर्पित करने के उपरांत ग्राम अमरेला से होते हुए फरीदनगर जाट कॉलोनी पर आकर समाप्त हुई इसमें लगभग 30 ट्रैक्टर 15 गाड़ियां और 40 मोटरसाइकिल व डीजे के साथ लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर, देशभक्ति गीत गाकर और नारों के माध्यम से पूरे वातावरण को राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। इस अवसर पर संजय कुमार चौहान एडवोकेट राष्ट्रीय महामंत्री (विधि प्रकोष्ठ) एवम नीतू सिंह अध्यक्ष (महिला मोर्चा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजन की सराहना की।भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के युवा जिला अध्यक्ष रोहित तोमर जी ने कहा, "हमारा उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और आजादी के शहीदों को याद करना है। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, हमारी अस्मिता का प्रतीक है।कार्यक्रम का समापन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करके हुआ। समापन कार्यक्रम में नीतू सिंह अध्यक्ष महिला मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। अध्यक्ष मेरठ मंडल युवा कुलदीप शर्मा जी ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से करते रहने की बात कही।

कार्यक्रम में हजारो की संख्या में पदाधिकारी रुपेश शर्मा, संगठन मंत्री मेरठ मण्डल , कुलदीप शर्मा, अध्यक्ष मेरठ मंडल युवा, अरविन्द चौधरी, तहसील अध्यक्ष , प्रेमचंद सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष भोजपुर, संजय कुमार चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री (विधि प्रकोष्ठ) , नीतू सिंह, अध्यक्ष महिला मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शशि तोमर, तहसील अध्यक्ष महिला मोर्चा मोदीनगर, अमरीना चाँद, महासचिव महिला मोर्चा मेरठ मण्डल, चंदा चौहान, नगर अध्यक्ष फरीदनगर, आदित्य पालीवाल, नगर महामंत्री फरीदनगर, रोहित तोमर, युवा जिला अध्यक्ष , सतेंद्र चौधरी, तहसील सचिव मोदीनगर, आदर्श सैनी, तहसील महासचिव मोदीनगर , असलम चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भोजपुर, मोहित तोमर, ब्लॉक उपाध्यक्ष भोजपुर , संजीव तोमर, नगर संगठन मंत्री, अमित शर्मा नगर प्रचार मंत्री , अफजल सैफी, नगर सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा , भव्यदीप चौहान, नगर उपाध्यक्ष , शमशाद खान, वरिष्ठ कार्यकर्त्ता , साहनवाज खान, कार्यकर्त्ता , इरशाद कुरैशी, कार्यकर्त्ता हमजा खान, कार्यकर्त्ता, हिमांशु शर्मा, कार्यकर्त्ता, कुंवर पाल सिंह, कार्यकर्त्ता , रामकिशन सैनी, कार्यकर्त्ता , सावेज खान, कार्यकर्त्ता , नविल खान, कार्यकर्त्ता , लोकेश तोमर, कार्यकर्त्ता , रोहित सोलंकी, कार्यकर्त्ता , सुक्की तोमर, कार्यकर्त्ता , दीपांशु शर्मा, कार्यकर्त्ता , पुष्पेंद्र चौधरी, हरेंद्र चौधरी, लोकेश चौधरी, जसबीर सिंह, कृष्ण सिंह, दीपक शर्मा, विपिन कुमार , विनीत कुमार, विकास तोमर, अर्जुन चौहान, मोहन सैनी, भार्गव चौहान, सुन्दर चौधरी, राहुल सैनी, सचिन कुमार, प्रेमपाल तोमर, भोपाल सैनी, सोहन पाल तोमर, डिम्पल शर्मा, अफजल खान, मनमोहन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश , मनीष गर्ग, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रभात तिवारी, एन सी आर मीडिया प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, निश्चल ढाका, जिला उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, देवेंद्र सक्सेना, जिला सचिव विधि प्रकोष्ठ, लोकेश गुप्ता, कार्यकर्त्ता, समरे आलम, जिला महासचिव विधि प्रकोष्ठ, शाकिर, ब्लॉक अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ भोजपुर, मुशरफ, जिला सचिव विधि प्रकोष्ठ, तौफीक, जिला सचिव, नवनीत कुमार, जिला सचिव विधि प्रकोष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

जसोमती - एक योद्धा मां और समाजसेविका की अमर कहानी

(जीएनएस)।

लखनऊ। 15 अगस्त की सुबह 3:30 बजे, ग्राम दिघिया, पोस्ट मौंदा, मोहान रोड, थाना काकोरी, लखनऊ निवासी श्रीमती जसोमती ने इस नश्वर संसार से अंतिम विदाई ली। उनकी उम्र मात्र 52 वर्ष थी। लेकिन इतनी कम आयु में भी उन्होंने अपने पीछे त्याग, संघर्ष और समाजसेवा की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।श्रद्धेय जसोमती जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे उन दिनों अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं जब घर में खाने को अनाज तक नसीब नहीं होता था। लेकिन मां होने का कर्तव्य उन्होंने हर हाल में निभाया। कई बार दूसरों के घरों से आटा, चावल, दाल, रोटी मांगकर लाकर अपने बच्चों को खिलाया, मगर खुद भूखी रह गईं। बारिश के दिनों में जब उनका कच्चा मकान टपकता था, तो वह अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए रातभर जागती रहीं। लेकिन जसोमती जी का संघर्ष केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा। उनका हृदय समाज के गरीबों और वंचितों के लिए हमेशा धड़कता रहा।

एक समय ऐसा आया जब एक संगठन से उन्हें पदाधिकारी बनाया गया। उसी दौरान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को बेघर किए जाने का मामला सामने आया। जसोमती जी ने निस्वार्थ भाव से कई महीनों तक धरना दिया, शासन-प्रशासन से तीखी बहस की और अंततः सैकड़ों गरीब किसानों को रहने के लिए दूसरी जगह जमीन दिलवाई। आज वही किसान अपने-अपने परिवार के साथ उस जगह पर घर बनाकर रह रहे हैं। जसोमती जी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। उनका जीवन पूरी तरह समाज की सेवा को समर्पित रहा। वे उन लोगों की आवाज बनीं, जिनकी कोई आवाज नहीं थी।आज भले ही जसोमती जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, उनका त्याग और उनकी निस्वार्थ सेवा हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। उनके परिवार के लिए वे एक अटूट मां थीं, और समाज के लिए एक साहसी समाजसेविका। जसोमती जी की स्मृतियां हर उस गरीब किसान और परिवार के साथ हमेशा जीवित रहेंगी, जिनके जीवन में उन्होंने उजाला भर दिया।

मॉडल बाल वाटिका परिसर में किया गया ध्वजारोहण।

(जीएनएस)।

एक तरफ जहां पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही जश्न के साथ मनाया गया वहीं दूसरी तरफ लखनऊ काकोरी क्षेत्र शिवरी में बने मॉडल बाल वाटिका परिसर में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम किया गया इस कार्यक्रम में ए.आर.डी मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र प्रसाद जी रामराज खंड शिक्षा अधिकारी काकोरी सी.डी.पी.ओ.अरविंद सिंह ग्राम प्रधान अंजनी राजपूत प्रधान प्रतिनिधि राम नरेश राजपूत ए.आर.पी.प्रधान काकोरी सचिव दीप कुमार बेसिक शिक्षा विद्यालय

पान खेड़ा प्रधानाध्यापिका अनीता जोशी व नीता संस्कृतिक कार्यक्रम अपनी टीम के साथ प्रस्तुत किए बेसिक विद्यालय खुशहालगंज श्रीमती अंजली सक्सेना व उनकी टीम द्वारा संस्कृतीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम वासी व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उपस्थित रहे यह कार्यक्रम काकोरी ब्लाक के शिवरी गांव मॉडल बाल वाटिका परिसर में संपन्न हुआ।

मुंबई में 4 दिन में 3 पुलिसकर्मियों ने किया सुसाइड, कानून के रखवाले क्यों दे रहे जान?

(जीएनएस)।

मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है. यहां कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर से आते हैं. कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मुंबई के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं होता. हालांकि, पिछले चार दिनों में मुंबई में हुई तीन दिल दहला देने वाली घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. मुंबई करों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसवालों ने ही आत्महत्या का कदम उठाकर अपनी जान दे दी. पिछले चार दिनों में तीन पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. हालांकि, इन तीनों पुलिसकर्मियों की आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिसकर्मियों की बढ़ती आत्महत्याएं चिंता बढ़ा रही हैं. इनमें से एक पुलिसकमीयों गोकुलाष्टमी के दिन यानी शनिवार को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक पुलिसकर्मी का नाम मुकेश देव (45) था. वह मरोल के सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. देव अंधेरी पूर्व में अगरकर बस अड्डे के पास पुलिस कॉलोनी में रहता था. घर में फांसी लगाकर कांस्टेबल ने दी जान शनिवार को हर तरफ गोकुलाष्टमी की धूम थी. हर कोई उत्साह के साथ त्योहार मना रहा था. टीमें दही हांडी फोड़ने की होड़ में थीं. जब हर कोई बाहर खुशी और उत्साह के साथ त्योहार मना रहा था तो कांस्टेबल मुकेश देव अपने घर में अकेले थे. शाम करीब चार बजे

मुकेश देव ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया और अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. जैसे ही आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और मुकेश देव को इलाज के लिए जुहू स्थित कूपर अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और सहायक पुलिस निरीक्षक जौंजाल जांच कर रहे हैं. चार दिनों में 3 पुलिस वालों ने किया सुसाइड पिछले चार दिनों में मुंबई में किसी पुलिसकर्मी द्वारा सुसाइड की यह तीसरी घटना है. शनिवार को मुकेश देव ने आत्महत्या कर ली थी. बुधवार, 13 अगस्त को कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी गणेश राउल (32) ने नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी.